केजरीवाल- सिर्फ मुख्यमंत्री या भावी प्रधानमंत्री

-अजातशत्रु

पहले ओडिसा में गैर उड़िया भाषी का मुख्यमंत्री बनना, फ़िर छत्तीसगढ़ में और अब झारखंड में गैर आदिवासी का मुख्यमंत्री बनना और भारतीय राजनीति में केजरीवाल का उदय एक ही प्रक्रिया की कड़ियां हैं। केजरीवाल भारतीय राजनीतिक में एक व्यक्ति के तौर पर नहीं उभरे हैं बल्कि नये राजनीतिक तरकश को लेकर आये हैं। यह बड़ा विडम्बनापूर्ण है कि आम आदमी पार्टी के नाम से राजनीति में आनेवाले केजरीवाल एक ऐसी राजनीति की शुरूआत कर रहे हैं। जिसमें आम आदमी की खास हिस्सेदारी नहीं होगी।

'आदिवासी राजनीति की पराजय' शीर्षक से अपने लेख में (जनसत्ता, 21 जनवरी) अनिल चमड़िया ने झारखंड में पहले गैर आदिवासी के मुख्यमंत्री बनने पर लिखा है कि यह भारतीय राजनीति से आदिवासियों का विस्थापन है। वस्तुत: यह एक पूरी पूंजीवादी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें धीरे-धीरे करके, आम आदमी यानी गरीब और कमजोर आदमी को राजनीति से अलग कर दिया जाता है। और इस विस्थापन और अलगाव की राजनीति को परिणिति पर पहुंचाने में केजरीवाल भी देर-सबेर हाथ बटायेंगे।

भारतीय राजनीति में गरीब आदमी का प्रभावशाली हस्तक्षेप 70 से 80 के दशकों तक ही दिखायी देता है। सन् सतहत्तर का जे.पी. आंदोलन इस हस्तक्षेप की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति था। उसी वक्त कम्युनिस्ट आंदोलन भी देश में अपने चरम पर दिखायी देता है। सन् 70 से 85 तक का दौर पूरे विश्व में एक ऐसा समय था जब कमज़ोर और ग़रीब जनता की मुक्ति की कोशिशें अपनी चरम पर थीं और स्वाभाविक ही इसका नेतृत्व कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टियां कर रही थीं। लेकिन सन् 85 के बाद जहां पूंजीवाद ने नयी परिस्थितियों से निपटने के लिये नयी रणनीतियां अपनाई वहीं कम्युनिस्ट आंदोलन आम जनता को कोई रास्ता नहीं दिखा पाया।

नतीजा सोवियत रूस के विघटन और कई अन्य देशों में कम्युनिस्ट शासन के अन्त के रूप में सामने आया। भारत में यह बदलाव एक तरफ़ दक्षिणपंथी के एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में उभरने में सामने आया तो दूसरी तरफ़ पूरी तरह वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की नीतियों पर चलने में दिखायी दिया। यही वह समय था जब सबसे पहले सरकारी कारखाने निजी हाथों में बेचने की वकालत की गयी, गरीब की सब्सिडी को बोझ बताया जाने लगा और अमेरिकी स्वर्ग के सुहाने सपने भारतीय मध्यम वर्ग को दिखाये जाने लगे। यही वह समय है जब भारतीय राजनीति से आम आदमी, कमजोर आदमी, दलित आदिवासी के विस्थापन की शुरूआत होती है। यहीं से भारतीय राजनीति आम आदमी के हाथ से फिसलकर अमरीका परस्त मध्यमवर्ग के हाथ में जाने की शुरूआत दिखायी देती है। यह राजीव गांधी और लालकृष्ण आडवाणी का समय था। और यह हरकिशन सिंह सुरजीत का भी समय था।

भारतीय राजनीति में सन् 1990 से 2008 तक के संक्रमण के दौर में एक तरफ़ जहां आम जनता सत्ता से ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें पाने की कोशिश कर रही थी तो दूसरी तरफ़ पूंजीपति सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर आम आदमी को सत्ता व राजनीति से दूर करने में लगा था। लेकिन विश्व पर अमेरिका की आक्रामक नीतियों ने पासा उसके पक्ष में पलट दिया। पहले झूठे आरोप लगाकर इराक पर हमला करके कब्जाना और फ़िर लीबिया मिश्र, टयूनिशिया सीरिया आदि में हमले व तख्ता पलट करके उसने पूरे विश्व में सन्देश दिया कि पूरे विश्व का वह एक छत्र राजा है। इससे पूरे विश्व के ग़रीबों व मुक्ति की आकांक्षी जनता में भयंकर निराशा फ़ैली। अमेरिका की इस मुहिम के अनुरूप भारत में भी सरकारें- चाहे वे कांग्रेस की हों या बी.जे.पी. की, आम जनता-दलित आदिवासी, मज़दूर, किसान-को पीटने में लगी थी। उनके आंदोलनों को कुचलकर उन्हें सन्देश दिया जा रहा था कि अब राजनीति में उनकी कोई जगह नहीं है। ओडिसा में पोस्को के ख़िलाफ़ आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, राजस्थान के किसान आन्दोलन उदाहरण हैं। इसी दौर की उपज ओडिसा में नवीन पटनायक और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हैं। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ में रघुबर दास और नवीनतम कड़ी के रूप में मोदी हैं।

अपने दस साल के शासनकाल में कांग्रेस सरकार चाहकर भी जितनी सेवा बड़े कारपोरेट घरानों की नहीं कर सकी उतनी मोदी ने छह महीने से भी कम समय में कर दी। ग़रीबों की लूट के लिये मुख्य तीन काम सबसे जरूरी थे-ग़रीब जनता से उसकी ज़मीन छीनना, मज़दूरों के हित के क़ानून खत्म करना और कोयला आदि प्राकृतिक संसाधनों की लूट आसान बनाना। जो मोदी गरीबों के हित के काम के लिये दस साल की मांग कर रहा है, छह महीने में उसके काम काज का हिसाब मांगने पर नाराज हो रहा है, उसे लोग़ों की लूट के लिये आठ अध्यादेश लागू करते हुये कोई समय लगा और न जरा सी शर्म आयी।

मोदी मुख्य रूप से मुस्लिम विरोध के आधार पर हिन्दू वोटों को इकट्ठा करके जीत कर आये। लेकिन दूसरी तरफ़ उन्होंने बीजेपी के सभी नेताओं को किनारे लगा सिर्फ़ अपने पर केन्द्रित चुनाव प्रचार के ज़रिये राजनीति के मुद्दों से हटाकर व्यक्ति केन्द्रित राजनीति में बदल लिया। इस काम में पूरे देश में भ्रष्ट कांग्रेस विरोधी माहौल और विश्व में अमेरिकी दादागिरी ने उनकी खूब मदद की। विश्व पूंजीवाद ने भी, गुजरात में मोदी की कार्यशैली के आधार पर भारत में पूंजीवाद के इस महान सेनापति को पहचान लिया और इसलिये अकारण नहीं है कि अमेरिका हो या जापान हर कोई दम ठोंककर मोदी के पीछे खड़ा है।

पूंजीवाद की कोशिश रहती है कि किसी भी देश में सिर्फ़ दो ही राजनीतिक पार्टियां हों और वे भी आर्थिक नीतियों में अलग न हों, ताकि डेमोक्रेसी के नाम का ढकोसला भी बना रहे और लोग़ों को वास्तव में कोई पूंजीवाद का विकल्प भी न मिले। इसी के तहत उसने कांग्रेस के बरक्स धीरे-धीरे बीजेपी को भारतीय राजनीति में स्थापित किया। लेकिन अब कांग्रेस अपनी विश्वसनियता इस कदर खो चुकी है कि एक विकल्प के रूप में पूंजीवाद के लिये उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर रह गई है। इसलिये जरूरी था कि एक और पार्टी को विकल्प के तौर पर तैयार किया जाये जो इन्हीं आर्थिक नीतियों के साथ बी जे पी की जगह लायी जा सके। इसी सुअवसर पर केजरीवाल भारतीय राजनीति ने उभरे।

गौरतलब है कि केजरीवाल विशुद्ध रूप से अमरीकी नकल पर अपनी पार्टी को चला रहे हैं। वहां की पार्टियों के अन्दरूनी चुनाव की तरह उम्मीदवारों का चुनाव, भोज पार्टी से चन्दा इकट्ठा करना, चुनाव प्रबन्धन पेशेवरों को सौंपना और सबसे महत्वपूर्ण है राजनीति को व्यक्ति केन्द्रित करना। और विभिन्न अवसरों पर वे यह जाता ही चुके हैं कि उनका आर्थिक नीतियों पर मोदी या कांग्रेस या अमरीका से कोई मतभेद नहीं है। इन्हीं सब खासियतों के चलते और उनकी हाजिर जवाबी के कारण वे जरूरत पड़ने पर, मोदी के विफल होने पर, उनके विकल्प के तौर पर अगले कुछ सालों में पेश किये जाये तो कोई अचरज नहीं होना चाहिए।

एन आई टी में जुआ सट्टा व सूदखोरी नहीं थम रही

फ़रीदाबाद (म.मो.) ने 16-31 जनवरी अंक में थाना एन.आई. टी पुलिस संरक्षण में पनपता अपराध शीर्षक नाम से खबर प्रकाशित की थी। सुधी पाठकों ने पढा होगा किस तरह थाना एन आई टी पुलिस कमिशनर के आदेशों को ठेंगा व पलीता लगाने में लगे हुए है। जो कमिशनर ने असामाजिक तत्वों पर लगाम लगा कर जनता को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए अपने अधिकारियों को दिए थे। अंक में थाना एन आई टी में तैनात एस आई सतपाल सिंह का थोड़ा सा विवरण भी किया था। जिसके सप्ताह भर बाद ही एस आई सतपाल सिंह का थाना एन आई टी से तबादला कर दिया गया जो पिछले काफ़ी अरसे से थाना एन आई टी में तैनाती के चलते बड़ी बेशर्मी के साथ अपने डंडे व कलम का इस्तेमाल करता था।

सर्वेक्षण व सूत्रों के अनुसार मज़दूर मोर्चा ने कुछ सट्टेबाज़ों, शराब माफ़ियों, जुआरियों, व सूदखोरों के नाम की प्रकाशित किए थे व एन.एच. 5 सी ब्लॉक में पाला सरदार के गोरख धंधों के बारे में भी पाठकों को बताया गया था कि एस एच ओ राम किशन व एस आई सतपाल सिंह से मिले खुले आशीर्वाद के चलते पाला सरदार बीच सड़क दिन-दहाड़े कुर्सी लगाकर सट्टे की पर्ची बेच रहा है। व शराब का धंधा भी कर रहा है। दिनांक 29.1.15 को 5 नम्बर डी ब्लाक निवासी ने बताया कि पाला सरदार खुले में सट्टे का कारोबार कर रहा है। जिसको लेकर बीच सड़क में सट्टा खेलने वालों की काफ़ी भीड़ इकट्ठा है। जिसको लेकर एक फ़ोटो ग्राफ़र व उसका साथी एन एच 5 ब्लॉक पहूंचा व एकत्रित भीड़ का फ़ोटो खींच लिया जिसको लेकर पाला सरदार उसका भाई व कुछ साथी फ़ोटो ग्राफ़र को रोक कर फ़ोटो कैमरे से हटाने का दबाव बनाने लग गए। जब फ़ोटो ग्राफ़र ने उनका दबाव नहीं माना तो पाला सरदार के सुर बदलते देर न लगी व वहां सट्टे खेलने वालों के सामने तेज़-चिल्लाने लगा कि मेरा सरगना एस एच ओ से लेकर सी पी कार्यालय तक मंथली बांटता है। तुम अखबार वालो ने जो छापना है छाप लो मुझे तो थाना एन आई टी में सट्टे व शराब का केस देना होता है। जो मैं देता रहता हूं।

उसके करीब आधे घंटे बाद पाला सरदार के मिलने वाले ने फ़ोटो ग्राफ़र के साथी को फ़ोन कर अपने कार्यालय बुलाया व उसे फ़ोटो खबर न छापने के लिये कहा उस पर फ़ोटो ग्राफ़र ने कहा कि जब सी पी ऑफ़िस तक मंथली जाती है तो डर काहे का व इस सारे प्रकरण को अपने स्तर पर डी सी पी एन आई टी व सी पी को फ़ोटो की मैसेज व मेल करूंगा तो पाला सरदार के मिलने वाले ने तुरंत पाले को फ़ोन कर कहा कि 5000 रुपये लेकर मेरे ऑफ़िस में आजा जिस पर पाला व उसके भाई भी वहां आ गये। लेकिन फ़ोटो ग्राफ़र व साथी ने रुपये नहीं लिये व बड़ी मुश्किल से अपना पिंड छुड़ा वहां से निकले ठीक।

इसी तरह एन एच 5 एम ब्लॉक में बने पार्क में संजीव उर्फ़ गाशी अपने गोरख धंधों को अंजाम दे रहा है। जबकि सुबह 9 बजे से लेकर देर रात तक इस पार्क में लाखों रुपये का जुआ खेला जाता है। व थाना एन आई टी पुलिस अपना हिस्सा वसूल कर ले जाती है। एन एच 5 एम ब्लॉक के आधा दर्जन लड़के संजीव उर्फ़ गाशी के लिए सारा लेन-देन का हिसाब व पर्ची लिखने का काम करते हैं। ये कोई अकेला पार्क नहीं है। जिसमें जुआ सट्टे का धंधा चलता है।

बल्कि डी सी पी एन आई टी कार्यालय के ठीक सामने बने पार्क में भी जम कर जुआ सट्टा चलता है व एन आई टी पुलिस के साथ -साथ सी आई ए वाले भी हिस्सा वसूलते हैं । ये सारा धंधा कोई चोरी-छिपे नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है।

सी पी सुभाष यादव की नियुक्ति के बाद ऑनलाइन कैसिनो के बड़े मगरमच्छों की गिरफ़्तारी के बाद कैसिनो संचालकों के कारण बर्बाद हो चुके परिवारों में उम्मीद जगी थी। लेकिन एन आई टी पुलिस की कार्य शैली के चलते एक दिन पुलिस कमिशनर को फ़जीहत का मुंह देखना पड़ेगा।

सूदखोरी के शिकार बलदेव कुमार निवासी एम ब्लॉक एन एच 5 ने सूदखोर संजीव उर्फ़ गाशी से तंग आकर कीट नाशक गोलियां खा ली थी जिसे बादशाहखान वालों अस्पताल ने दिल्ली रेफ़र कर दिया था। जहां उसकी जान बड़ी मुश्किल से बच पाई।

इस मामले में दिनांक 15.6.14 को पुलिस ने एक रपट रोजनामचा लिख कर अपने कर्त्तव्य की इति श्री कर ली।

बलदेव ने गाशी से मात्र 20 हज़ार रुपये का कर्ज़ लिया था जिसके बदले वह 40 हज़ार रुपये उसको लौटा भी चुका है लेकिन उसके बावजूद मूल धन ज्यों का त्यों उसके सिर पर खड़ा है।

फैज की एक नज्म आज के अंधेरे दौर पर

सामंतवाद से लड़ाई के अपने यौवन-काल में पूंजीवादीलोकतंत्र के पुरोधाओं में से एक, वाल्तेयर ने कहा था कि मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी बात ग़लत है, लेकिन उस बात को कहने का तुम्हारा अधिकार बरकरार रहे, इसके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं।

पूंजीवाद के बुढ़ापे के युग में या विकृत-विकलांग पूंजीवादी समाजों में ऐसी बातें बीते जमाने की बात हो चुकी हैं। हर जगह जुबानों पर ताला, हर जगह स्वतंत्र विचारों के कातिल। व्यवस्था के चाटुकार साहित्यकार, भाड़े की कलम के कुली-कबाड़ी इस कुकर्म में निर्लज्ज सहभागी बने हुए हैं। इस बात पर फ़ैज की एक छोटी सी नज्म बेहद मौजूं है।

इधर न देखो
के जो बहादुर के कलम के: या तेग के धनी थे
जो अज्मो-हिम्मत के मुद्दई थे
अब उनके हाथों में सिद्क ईमां की
आजमूद: पुरानी तलवार मुड़ गयी है
जो कज कुलह साहबे-चश्म थे
जो अहले-दस्तार मोहतराम थे
हविस के परपेंच रास्तों में
कुलह किसी ने गिरो रख दी
किसी ने दस्तार बेच दी है
उधार भी दखो
जो अपने रख्शां लहू के दीनार
मुफ़्त बाजार में लुटा कर
नज़र से ओझल हुए
और अपनी लहद में इस वक्त तक गनी हैं।
उधर भी देखो
जो सिर्फ़ हक की सलीब पर अपना तन सज़ा कर
जहां से रुकसत हुए
और-अहले जहां में इस वक्त तक बनी हैं।

देश-विदेश

मंझावली यमुना पुल का ड्रामा फ़िर शुरू, इस बार मैट्रो रेल भी साथ में

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब 7 माह पूर्व भाजपा के केन्द्रीय सड़क परिवहन मन्त्री नितिन गडकरी व स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फ़रीदाबाद को नौयडा से जोड़ने के लिये यमुना पर 6 लेन पुल बनाने के नाम पर अच्छा खासा ड्रामा करके घोषणा की थी कि 2 वर्ष में पुल बनकर चालू हो जायेगा। उस वक्त 'मज़दूर मोर्चा' ने सुधी पाठकों को बताया था कि 2 साल में पुल बनना तो दूर पुल की डी पी आर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) ही बन जाय तो बड़ी बात होगी।

7 माह बाद अब कहीं जाकर हरियाणा सरकार ने डी पी आर बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिये 10 करोड़ रुपये भी स्वीकृत कर दिये गये हैं। वास्तव में मौके पर डी पी आर बननी कब शुरू होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी ही डी पी आर उत्तर प्रदेश की तरफ़ भी बननी है। जब दोनों ओर की डी पी आर बन जायेंगी तब दोनों ओर सड़क निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया जायेगा। भूमि पर कब्ज़ा मिलने की बाद दोनों ओर की सड़कों व पुल का निर्माण कार्य शुरू हेना संभव होगा। जिस मंथर गति से भाजपा की राज्य एवं केन्द्र सरकार चल रही हैं उसे देखते हुए लगता नहीं कि आगामी डेढ साल में डी पी आर व भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो सके।

दरअसल यह सब राजनीतिक ड्रामेबाज़ी है आम जनता को बहलाये रखने के लिये। सात माह पहले यह ड्रामा विधानसभा चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिये रचा गया था और अब लोग़ों का ध्यान उनकी मूल समस्यायें शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली आदि से भटकाने के लिये है। मंधावली, मंझावली, भैंसरावली, कोराली व तिगांव आदि दर्जनों बड़े-बड़े गांव शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह महरूम हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं हैं तो अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। इन दोनों कामों के लिये जनता निजी शिक्षा व चिकित्सा व्यापारियों पर ही पूरी तरह निर्भर है। सड़कें, परिवहन, पशु चिकित्सा आदि का तो अब ज़िक्र करना ही बेमानी हो गया है।

यमुना पुल के अलावा कृष्णपाल ने अब फ़रीदाबाद- गुड़गांव मैट्रो रेल मार्ग से जोड़ने का शगूफ़ा भी हवा में छोड़ दिया है। किसी एक अख़बार में तो इसका रूटमैप (बड़खल चौक, सिद्धादाता आश्रम, मानव रचना व सूरजकुंड होते हुए महरोली आदि) भी छपवा दिया। विदित है कि मैट्रो रेल कार्पोरेशन दिल्ली व केन्द्र सरकार के आधीन है। यह कोई भी हवाई किलेबंदी नहीं करती। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मैट्रो रेल वाले डी पी आर व बजट के अलावा उसकी सार्थकता का आंकलन करते हैं। फ़िलहाल मैट्रो रेल ने इस तरह के किसी आंकलन पर न तो कोई काम किया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास विचाराधीन है। फ़िलहाल यह मात्र भाजपा सरकार की शिगूफ़ेबाज़ी है जिसके द्वारा जनता का ध्यान मूल समस्याओं से भटकाया जा सके तथा लगे हाथ प्रॉपर्टी के दामों को भी उछाला जा सके।